भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3184
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

स्मार्ट पीडीएस योजना

3184. श्री भारत सिंह कुशवाह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) योजना प्रायोगिक परियोजना के रूप में किन जिलों और राज्यों में शुरू की गई है;
(ख) स्मार्ट पीडीएस योजना और वर्तमान पीडीएस योजना में क्या अंतर है;
(ग) स्मार्ट (पीडीएस) के लाभार्थियों, जनता और विभाग को क्या लाभ होगा और वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन में क्या खामियां हैं;
(घ) क्या स्मार्ट पीडीएस योजना को पूरे देश में लागू किए जाने की संभावना है;
(ड.) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और
(च) उस निकाय का नाम क्या है जिसके माध्यम से इसे चलाया जाएगा?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): यह विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना (सीएसएस) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट-पीडीएस)" को लागू कर रहा है। वर्तमान में, स्मार्ट-पीडीएस विकास के चरण में है। यह परियोजना एनआईसी द्वारा अक्टूबर 2024 से शुरू की गई थी और इसके एप्लीकेशन को अप्रैल 2025 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने की संभावना है।

...2/-

स्मार्ट-पीडीएस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करना है, ताकि एनएफएसए और राज्य योजनाओं को कवर करते हुए पूरे पीडीएस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों और परिवर्तनकारी बदलावों का नेतृत्व किया जा सके। इस प्रकार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के संबंध में पीडीएस संचालन की राज्य स्तरीय तकनीकी सीमाओं को दूर करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन के कामकाज में लाए जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को बनाए रखने और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस से संबंधित सभी संचालनों को कवर करने वाली एक एकीकृत केंद्रीय प्रणाली को संस्थागत बनाने के लिए स्मार्ट-पीडीएस शुरू किया गया है।

(ग): स्मार्ट पीडीएस प्रणाली के आधुनिकीकरण प्रयासों से देश के सभी पीडीएस लाभार्थी लाभान्वित होते हैं। वर्तमान में, एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ के कुल लक्षित कवरेज की तुलना में, 80.56 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जो कुल कवरेज का लगभग 99.03% है।

(घ) से (च): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस विभाग द्वारा स्मार्ट-पीडीएस योजना शुरू की गई है और इसे लागू किया जाना है। वर्तमान में, इस विभाग ने स्मार्ट-पीडीएस योजना के लिए 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु को छोड़कर, जो प्रक्रियाधीन है) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, स्मार्ट पीडीएस का विकास प्रगति पर है और इसके एप्लीकेशन को अप्रैल 2025 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने की उम्मीद है। एनआईसी, स्मार्ट पीडीएस का तकनीकी भागीदार और डेवलपर भी है।

*****